भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

26.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4201 का उत्तर

एनईआर में समर्पित माल ढुलाई गलियारे

4201. श्री गौरव गोगोई:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में प्रस्तावित या नियोजित समर्पित माल ढुलाई गलियारे (डीएफसी) की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एनईआर में डीएफसी के निर्माण के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) वित्त वर्ष 2025 के लिए रेल अवसंरचना बजट के अंतर्गत एनईआर में माल ढुलाई गलियारे के विकास के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और भावी वित्तपोषण संबंधी योजनाएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने एनईआर में प्रस्तावित डीएफसी के लिए कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो वनों की कटाई, जैव-विविधता के प्रभाव और सरकार द्वारा नियोजित उपशमन उपायों के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल मंत्रालय ने दो समर्पित माल गलियारों अर्थात् लुधियाना से सोननगर (1337 कि.मी.) तक पूर्वी समर्पित माल गलियारा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से दादरी (1506 कि.मी.) तक पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के निर्माण का कार्य शुरू किया है। कुल

2843 कि.मी. में से, 2741 मार्ग किलोमीटर (96.4%) को कमीशन किया गया है और परिचालित किया जा रहा है। शेष खंड का कार्य शुरू कर दिया गया है।

रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन (03) नए समर्पित माल गलियारों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है:-

(i) पूर्व-तट गलियारा: खड़गपुर से विजयवाड़ा

(ii) पूर्व-पश्चिम गलियारा:

(क) पालघर-भुसावल-नागपुर-खड़गपुर-दानकुनी

(ख) राजखरसवां-कालीपहाड़ी-अंडाल

(ii) उत्तर-दक्षिण उप-गलियारा: विजयवाड़ा-नागपुर-इटारसी

उपरोक्त तीन गलियारों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

उपरोक्त तीन समर्पित माल गलियारों में से किसी भी गलियारे को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। समर्पित माल गलियारा परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी प्रधान परियोजनाएं हैं और किसी भी समर्पित माल गलियारा परियोजना की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता, यातायात की मांग और निधियों एवं वित्तीय विकल्पों की उपलब्धता आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपर्कता में सुधार लाने के लिए, अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 74,972 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 1,368 कि.मी की 18 रेल परियोजनाएं (13 नई लाइनें और 05 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 313 किलोमीटर लंबाई कमीशन की जा चुकी है और मार्च 2024 तक 40,549 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इनमें शामिल हैं:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	13	896	81	34,616
दोहरीकरण	5	472	232	5,933
कुल	18	1368	313	40,549

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की कमीशनिंग नीचे दी गई है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	333 कि.मी	66.6 कि.मी/वर्ष
2014-24	1728 कि.मी	172.8 कि.मी/वर्ष (लगभग 3 गुना)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने आने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए औसत बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹2,122 करोड़/वर्ष
2025-26	₹10,440 करोड़ (लगभग 5 गुना)

******